



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3814]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/आश्विन 5, 1940

No. 3814]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4992(अ).**—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी पानी और संबद्ध रसायन तथा आणविक उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 28 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हों,

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1365(अ), तारीख 26 मार्च, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 29 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अंतिम बार उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों की सेवाओं को तारीख 29 सितम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2018

**S.O. 4992(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial establishments to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 29th March 2018 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1365(E), dated the 26th March, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 29th September, 2018.

[F.No. S-11017 / 3 / 97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.